

मैसर्स मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

बनाम

भारतीय संघ

(सिविल अपील क्रमांक 1338/2017)

अप्रैल 24, 2017

[ए.के.सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 11 सी - केंद्र सरकार को इस आशय की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है कि प्रचलित प्रथा के मद्देनजर करदाताओं द्वारा देय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा - ऐसी अधिसूचना जारी न करना - क्या न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिया जा सकता है - की अनुमति- माना गया: अधिसूचना u/s.11 C जारी करना अधीनस्थ कानून की प्रकृति में है - सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने का निर्देश देना एक विशेष तरीके से नीतिगत निर्णय लेने के समान होगा, जो अस्वीकार्य है - जब धारा 11 के तहत केंद्र सरकार को इस आशय की अधिसूचना जारी करने की 'शक्ति' दी जाती है कि उत्पाद शुल्क की वसूली न की जाए या अधिनियम के तहत सामान्य रूप से देय राशि से कम शुल्क की वसूली की जाए, तो यह निर्णय लेने के लिए कि ऐसी अधिसूचना जारी की जाए या नहीं, सरकार के मन में विभिन्न विचार हो सकते हैं - यह पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है - केवल इसलिए कि उक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तें संतुष्ट हैं, ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई कारण नहीं होगा - जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी को वह कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे उसे प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकार के तहत करने का अधिकार दिया गया है -

इसके अलावा, तथ्यों पर भी, उत्पाद शुल्क नहीं लगाने की सामान्य प्रथा के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले संतुष्ट होने की शर्त - राजस्व की दलील है कि यह सरकार की नीति है कि अधिसूचना यूएलएस.11 सी जारी न की जाए जब इससे केवल कुछ निर्धारितियों को लाभ होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में, वैध और उचित पाया गया - प्रशासनिक कानून - अधीनस्थ कानून।

धारा 11 (सी) - अपीलकर्ता ने उत्पाद शुल्क का भुगतान किया - हालांकि, अधिसूचना जारी करने की मांग करके, रिफंड का दावा किया। जेजेसी - आयोजित: एस.जेजेसी उन स्थितियों पर विचार करता है जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है - यह उस स्थिति को कवर नहीं करता है जहां शुल्क का भुगतान किया जाता है और उस पर फिर से जुर्माना लगाया जाना है।

प्रशासनिक कानून - न्यायिक समीक्षा का दायरा - प्रशासनिक कार्रवाई की तुलना में अधीनस्थ कानून - के बीच अंतर - चर्चा की गई।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 14 - उल्लंघन - जब नहीं - अपीलकर्ता की दलील कि केंद्र सरकार द्वारा धारा 11 (सी) के तहत अधिसूचना जारी न करना अनुच्छेद 14 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन है - माना गया: यदि कुछ इकाइयां कुछ कारणों से उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचने में सक्षम थीं, तो अपीलकर्ता यह नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 14 का उपयोग करके उससे कोई शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए - यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड एक सकारात्मक अवधारणा है और इसे नकारात्मक में लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए माना:

1. जब सभी तथ्यों को समग्रता से ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की गई, तो यह स्पष्ट है कि उत्पाद शुल्क नहीं लगाने की सामान्य प्रथा के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अपीलकर्ता का पूरा प्रयास अधिनियम की धारा 11 सी के तहत एक अधिसूचना जारी करने की मांग करके उक्त शुल्क वापस वसूल करना है। ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जा सकता. [पैरा 28, 29] [424-ए, ई]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर बनाम गुरुकृपा रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड (2011) 13 एससीसी 180: [2011] 8 एससीआर 178 - पर भरोसा किया गया।

2.1 जहां तक ऐसी अधिसूचना जारी करने के सरकार के दायित्व पर आधारित तर्क का संबंध है, प्रशासनिक क्षमता में कार्य करने के कर्तव्य और वैधानिक कार्य करने की शक्ति के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को कोई कार्य करने के लिए कोई कर्तव्य सौंपा गया है और वह उस कार्य का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो उक्त प्राधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। हालाँकि, यह किसी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय किया जाता है। यह किसी विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा से बिल्कुल अलग है। [पैरा 30] [424-जी-एच]

2.2 अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी करना अधीनस्थ कानून की प्रकृति में है। सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने का निर्देश देना एक विशेष तरीके से नीतिगत निर्णय लेने जैसा होगा, जो अस्वीकार्य है। जब केंद्र सरकार को इस आशय की अधिसूचना जारी करने की 'शक्ति' दी जाती है कि उत्पाद शुल्क की वसूली न की जाए या अधिनियम के तहत सामान्य रूप से देय शुल्क से कम शुल्क की वसूली की जाए, तो यह तय करने के लिए कि ऐसी अधिसूचना जारी की जाए या नहीं, सरकार के मन में कई तरह के विचार हो सकते हैं. केवल इसलिए कि उक्त प्रावधानों में

निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हैं, ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई कारण नहीं होगा। यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है। जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी विधायिका के प्रत्यायोजित अधिकार के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी को कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे उसे प्रत्यायोजित विधायी अधिकार के तहत करने का अधिकार दिया गया है। [पैरा 32, 33, 36] [425-डी-ई; 428-सी-डी; 427-सी]

2.3 प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों में न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति निश्चित रूप से तब मौजूद होती है जब यह पाया जाता है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण/कार्यकारी अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। हालाँकि, अधीनस्थ कानून के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। जहां कानून एक प्रशासनिक प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, न्यायालय ऐसे विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह अप्रत्यक्ष अंत या बाहरी उद्देश्यों या बाहरी विचारों पर या मनमाने ढंग से, प्रासंगिक विचारों पर अपना दिमाग लगाए बिना नहीं किया जाता है या जहां यह किसी भी मानदंड द्वारा निर्देशित नहीं है जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। [पैरा 35,36] [428-बी, ई-एफ)

जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम आर. कृष्णमूर्ति (2015)2 एससीसी 796: [2014) 11 एससीआर 463; सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1989) 4 सेकंड 187: [1989) 3 एससीआर 488; सामान्य कारण बनाम भारत संघ और अन्य (2003) 8 एससीसी 250: [2003) 4 सप्ल.एससीआर 471 - पर भरोसा किया गया।

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र, बॉम्बे बनाम भारत संघ (1985) 1 एससीसी 641: [1985) 2 एससीआर 287 - संदर्भित।

2.4 प्रतिवादी का यह स्पष्ट रुख है कि सरकार की नीति अधिनियम की धारा यूसी के तहत अधिसूचना जारी नहीं करना है, जब इससे केवल कुछ निर्धारितियों को लाभ होता है। कहा गया है कि सरकार की विशिष्ट नीति यह है कि जब व्यापार का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है और कोई राहत देने का प्रस्ताव होता है, तो अधिनियम की धारा 11 सी के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है। जब सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग न करने के कारणों को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, अर्थात्, ऐसी अधिसूचना, यदि जारी की जाती है, तो केवल दो इकाइयों को लाभ होने वाली है, वही वैध और उचित पाई गई है। [पैरा 37] [428-एफ-एच]

मैट्रिया केमिकल्स लिमिटेड आदि आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि आदि (2004) 4 एससीसी 311: (2004] 3 एससीआर 982 - पर भरोसा किया गया।

अंबिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य। (1987) 1 एससीसी 213: (1987] 1 एससीआर 562; धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और अन्य। (2007) 8 एससीसी 338: (2007] 10 एससीआर 245; डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2015) 8 एससीसी 744: (2015] 7 एससीआर 814; अनीश डी. लावंडे और अन्य बनाम गोवा राज्य और अन्य (2014) 1 धारा 554: (2013] 17 एसईआर 55; सुरेश चंद गौतम बनाम गोवा राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य (2016) 11 एससीसी 113: [2016] 1 एसईआर 727; चोकसी ट्यूब कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 11 सेकंड 179; भारत संघ और अन्य बनाम एन.एस. रत्नम एंड संस [2015] 8 एससीआर 751 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड और एएम के लॉर्ड बिशप: 1880 (5) ए.सी. 214 - अनुचित ठहराया गया।

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स,
डीडवाना, राजस्थान (1991) 4 एससीसी 473: [1991] 1 सप्ल.एसईआर 124 -
संदर्भित।

डी स्मिथ द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा - का उल्लेख किया
गया है।

केस कानून संदर्भ

[2011] 8 एससीआर 178	निर्भर	पैरा 7, 29
1880 (5) ए.सी. 214	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 17
[1987] 1 एससीआर 562	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 17
[2007] 10 एससीआर 245	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 18
(2015) 7 एससीआर 814	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 18
(2013) 17 एससीआर 55	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 18
(2016) 1 एससीआर 727	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 18
(1997) 11 सेक 179	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 19
(2015) 8 एससीआर 751	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 19
(1991) 1 सप्ल.एससीआर 124	संदर्भित	पैरा 26
(2014) 11 एससीआर 463	निर्भर	पैरा 32
[1989] 3 एससीआर 488	निर्भर	पैरा 33
[2003] 4 सप्ल.एससीआर 471	निर्भर	पैरा 34
[1985] 2 एससीआर 287	संदर्भित	पैरा 35

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1338/2017

WP (C) संख्या 2885/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 16.02.2016 से।

अपीलकर्ता के लिए एस. गणेश, वरिष्ठ वकील, प्रशांत भूषण, रोह आईटी कुमार सिंह, वकील।

ए.के. सांघी, वरिष्ठ वकील, सुश्री सुनीता रानी सिंह, रितिन राय, बी. कृष्णा प्रसाद, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए.के. सीकरी, सी.जे.आई.

यह अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें अपीलकर्ता चाहता था कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे और केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 सी के तहत एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करें कि उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर अपीलकर्ता द्वारा देय शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा.

2. अधिनियम की धारा 11 सी इस प्रकार है:

"11 सी. सामान्य प्रथा के परिणामस्वरूप नहीं लगाए गए या कम लगाए गए उत्पाद शुल्क की वसूली न करने की शक्ति-

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है-

(ए) कि किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क (उसके गैर-लगान सहित) लगाने के संबंध में एक प्रथा आम तौर पर प्रचलित थी या है; और

(बी) कि ऐसे सामान उत्तरदायी थे, या हैं-

(i) उत्पाद शुल्क के लिए, ऐसे मामलों में जहां उक्त प्रथा के अनुसार शुल्क नहीं लगाया गया था, या नहीं लगाया जा रहा है, या

(ii) उक्त प्रथा के अनुसार, जो उत्पाद शुल्क लगाया गया था, या लगाया जा रहा है, उससे अधिक राशि के लिए, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे माल पर देय संपूर्ण उत्पाद शुल्क, या, जैसा भी मामला हो, ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क से अधिक उत्पाद शुल्क, लेकिन उक्त प्रथा के लिए, उस माल के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस पर उक्त प्रथा के अनुसार उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया था, या नहीं लगाया जा रहा है, या कम लगाया जा रहा है।

(2) जहां किसी माल के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई अधिसूचना जारी की गई है, ऐसे माल पर भुगतान की गई संपूर्ण उत्पाद शुल्क या, जैसा भी मामला हो, ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क से अधिक भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क, जिसका भुगतान नहीं किया गया होता, यदि उक्त अधिसूचना लागू थी, तो लागू होने के अनुसार निपटा जाएगा, धारा 11बी की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा:

बशर्ते कि ऐसी इयूटी या अतिरिक्त इयूटी की वापसी का दावा करने वाला व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, धारा 11बी की उपधारा (1) में निर्दिष्ट फॉर्म में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर को इस संबंध में एक आवेदन करता है, उक्त अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले।"

3. उपरोक्त प्रावधान का एक मात्र अवलोकन यह संकेत देगा कि यदि उसमें उल्लिखित कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं, तो केंद्रीय सरकार एक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें निर्देश दिया जा सकता है कि ऐसे सामानों पर देय संपूर्ण उत्पाद शुल्क, या, जैसा भी मामला हो, ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क से अधिक, लेकिन उक्त प्रथा के लिए, भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त धारा में निर्धारित शर्त जिसके साथ केंद्र सरकार को खुद को संतुष्ट करना है वह यह है कि आम तौर पर प्रचलित प्रथा है जिसके अनुसार शुल्क नहीं लगाया गया था, या नहीं लगाया जा रहा है, तब भी जब ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क अन्यथा देय था।

4. हम इस स्तर पर ही बता सकते हैं कि उच्च न्यायालय अपने फैसले के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम की धारा 11 सी सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने या न जारी करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है। उक्त प्रावधान सरकार को अनिवार्य रूप से ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है और इस संबंध में सरकार की ओर से किसी भी दायित्व के अभाव में, न्यायालयों को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने और अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को कोई भी आदेश देने से रोक दिया गया है।

5. इससे पहले कि हम ऊपर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें और उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण की शुद्धता या अन्यथा पर टिप्पणी करें, उन मौलिक और भौतिक तथ्यों को बताया जाना चाहिए, जिनका मुद्दे पर असर पड़ता है। ये तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता रोसिन और टर्पेन्टाइन के निर्माण के व्यवसाय में हैं। रोसिन, पाइन ट्री की विभिन्न प्रजातियों से निकलने वाले ओलेओरेसिन का रालयुक्त घटक है, यानी ओलेओ पाइन रेजिन, जिसे वाणिज्य में 'क्रूड टर्पेन्टाइन' के रूप में जाना जाता है।

तारपीन और रोसिन के आवश्यक तेल स्पिरिट में ओलेरोसिन का पृथक्करण बड़े केतली स्टिल में आसवन द्वारा किया जाता है। ओलेओ पाइन रेज़िन से रोज़िन/तारपीन के निर्माण की दो विधियाँ हैं। एक विधि वैक्यूम रासायनिक उपचार प्रक्रिया है जो लगभग सभी प्रक्रियाओं में शक्ति का उपयोग करती है। दूसरी विधि, जिसे आमतौर पर भट्टी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, संघनन के उद्देश्य से पानी को भंडारण टैंक तक उठाने के लिए पंप को संचालित करने के लिए बिजली के उपयोग को छोड़कर पूरी तरह से मैनुअल है। इस प्रकार, दूसरी विधि में, बिजली का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह पानी को संघनित करने के उद्देश्य से भंडारण टैंक तक उठाने के लिए पंप के संचालन तक ही सीमित है। अपीलकर्ता रोसिन/तारपीन के निर्माण की इस दूसरी विधि का उपयोग कर रहा है।

6. जहां तक रोसिन/तारपीन के निर्माण की पहली विधि का संबंध है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं में बिजली का उपयोग किया जाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसे बिजली की सहायता से एक विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में माना जाता है और इकाइयां इस पद्धति का उपयोग करके या अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले इन उत्पादों का निर्माण कर रही थीं। लगभग दस इकाइयाँ हैं जो इस पद्धति को अपना रही हैं और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं पर अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रही हैं।

7. अधिकांश इकाइयाँ, यानी लगभग 300 की संख्या में, भट्टी पद्धति का उपयोग कर रही हैं, जिसके तहत बिजली का उपयोग टैंकों में तरल तारपीन के रूप में एकत्र तारपीन वाष्प के संघनन के लिए ओवरहेड टैंकों तक पानी उठाने तक सीमित है। केतली में जो रोसिन रहता है उसे बाल्टियों में निकाला जाता है, आमतौर पर ठंडा किया जाता है और ड्रमों में भेजा जाता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि इस प्रक्रिया को भी बिजली की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में

माना जाएगा, भले ही ऐसी शक्ति का उपयोग सीमित सीमा तक किया जाता हो। वह निर्णय केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर बनाम गुरुकृपा रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड' में बताया गया है, जो 11. 07.2011 को दिया गया था, जिसके तथ्य पर त्वरित अपील की घटनाओं के अनुक्रम से निपटने के दौरान फिर से चर्चा की जाएगी।

8. इस स्तर पर जिस बात पर जोर दिया गया है वह यह है कि यह पार्टियों का एक सामान्य मामला है कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अन्यथा, कानून में देय है। जहां तक इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के इतिहास का सवाल है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि अधिसूचना संख्या 179/77-सीई दिनांक 18.06.1977 के तहत, केंद्र सरकार ने ऐसे सामानों के निर्माण के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम (1944 के प्रथम) की पहली अनुसूची के आइटम नंबर 68 के तहत आने वाले सभी सामानों को छूट दी थी, जहां कोई भी प्रक्रिया आम तौर पर शक्ति की सहायता से नहीं चलती है, उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से। राजस्व विभाग ने दिनांक 16.01.1978 को इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया था कि उपरोक्त अधिसूचना उन इकाइयों को कवर करती है जो रोजिन और तारपीन तेल का निर्माण कर रही हैं, जहां रोजिन के निर्माण में कोई बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन बिजली का उपयोग टैंक में पानी खींचने के लिए किया जाता है, जिससे तेल वाष्प युक्त कुंडलियाँ गुजरती हैं। यह अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। हालाँकि, इस अधिसूचना को 01.03.1986 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जिससे उपरोक्त छूट वापस ले ली गई थी। इसके बाद 27.05.1994 के परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि पुराने टैरिफ के संदर्भ में मार्च 1986 से पहले जारी किए गए सभी परिपत्र/निर्देश/टैरिफ सलाह वापस ले ली गई थीं।

9. उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 04.10.2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा निर्मित और 01.04.1999 से 31.08.2003 की अवधि के दौरान स्वीकृत उपरोक्त उत्पादों पर 10,91,99,456/- रुपये शुल्क की मांग की गई थी। . इसके बाद सितंबर-अक्टूबर, 2003 से मार्च, 2004 की अवधि को कवर करते हुए इसी आशय की अन्य सूचनाएं जारी की गईं; अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2004; और दिसंबर, 2004 से सितंबर, 2005 तक क्रमशः रु. 50,760/-, रु.66,44,602/-, रु.1,01,92,867/- और रु.81,44,105/- की राशि। एक अन्य इकाई मेसर्स गुरुकृपा रजिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर (संक्षेप में 'गुरुकृपा') को भी इसी तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपीलकर्ता का मामला यह है कि भट्टी पद्धति का उपयोग करने वाली 300 इकाइयों में से केवल इन दो इकाइयों को उत्पाद शुल्क की मांग बढ़ाने के लिए चुना गया था।

10. गुरुकृपा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (संक्षेप में 'CESTAT') के समक्ष अपील दायर करके अपने मामले में पारित मूल्यांकन के आदेश को चुनौती दी थी। दिनांक 14.01.2004 के निर्णय के तहत गुरुकृपा की उक्त अपील को स्वीकार कर लिया गया। विभाग ने गुरुकृपा के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें राजस्व सफल हुआ क्योंकि इस न्यायालय ने अपने फैसले दिनांक 11.07.2011 के तहत अपील की अनुमति दी थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11. इस न्यायालय ने माना कि क्लिंग टैंक में पानी उठाने की प्रक्रिया इन वस्तुओं के निर्माण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी और इसलिए, यदि बिजली का उपयोग पानी उठाने के लिए किया गया था, तो छूट उपलब्ध नहीं होगी। इस न्यायालय ने यह भी माना कि टीआरयू का 1978 का परिपत्र लागू नहीं था क्योंकि इसे 1994 में वापस ले लिया गया था।

12. गुरुकृपारेसिन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिए गए उपरोक्त फैसले के मद्देनजर, CESTAT के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने भुगतान को केवल सीमा अवधि के भीतर, यानी एक वर्ष की अवधि के लिए आने वाले बकाया की वसूली के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इससे उत्पाद शुल्क की मांग में भारी कमी आई क्योंकि 01.04.1999 से 31.08.2003 की अवधि के लिए मांगी गई उत्पाद शुल्क कालातीत हो गई। विभाग और अपीलकर्ता दोनों ने CESTAT के उक्त आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है और मामला अभी भी वहां लंबित है।

13. गुरुकृपा रेंजिन्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के बाद, कई व्यापार संघों ने जी अधिनियम की धारा 11 सी के तहत लाभ देने के अनुरोध के साथ सरकार को अभ्यावेदन दिया। इन अभ्यावेदनों को प्राप्त करने पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने 27.05.1994 से 27.02.2006 की अवधि के दौरान एक सामान्य अभ्यास का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप सर्वेक्षण पत्र दिनांक 14.03.2012 को जारी किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क न लगाने की कोई प्रथा नहीं है। उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर इस आधार पर आपत्तियां उठाई गईं कि सर्वेक्षण में लगभग 300 की कुल इकाइयों के मुकाबले केवल दस इकाइयों पर विचार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.01.2013 को पत्र द्वारा पुनः सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। अपीलकर्ता के अनुसार, इस पुनः सर्वेक्षण से पता चला कि हालांकि देश भर में कई इकाइयां थीं जिनका कारोबार एसएसआई से अधिक था, लेकिन उन पर उपरोक्त अवधि के दौरान कभी भी उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया था, और यह घटना यह स्थापित करती है कि भट्टी पद्धति का उपयोग करने वाली इकाइयों

से उत्पाद शुल्क की मांग न करने की एक सामान्य प्रथा थी। अपीलकर्ता की यह दलील तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं, इस पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी।

14. मामले का तथ्य यह है कि गहन विचार के बाद, वित्त मंत्रालय ने 15.09.2014 को अधिनियम की धारा 1 एलसी के तहत ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि इससे केवल दो कंपनियों को लाभ होने वाला था, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है। यह निर्णय राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2014 के पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय निर्माता संगठनों को सूचित किया गया था। उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की:

"(ए) निर्णय को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी या किसी अन्य समान रिट या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी के पत्र दिनांक 30.09.2014 के माध्यम से सूचित किया गया हो। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 सी के तहत बिजली की सहायता के बिना रोजिन और तारपीन का निर्माण करने वाली इकाइयों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है। 27.05.1994 से 28.02.2006 की अवधि के लिए, ओवरहेड टैंक में संघनन के लिए पानी उठाने के लिए, पंप करने के लिए यूसिरिंग बिजली के उद्देश्य को छोड़कर, भले ही विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में उक्त अवधि के लिए इन इकाइयों पर गैर-उगाही की प्रथा पहले ही स्थापित की जा चुकी है;

(बी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश या किसी अन्य समान रिट या निर्देश जारी करें। 27.05.1994 से 28.02.2006 तक की अवधि के लिए, ओवरहेड टैंक तक पानी उठाने के लिए पंप में बिजली का उपयोग करने के उद्देश्य को छोड़कर, बिजली की सहायता के बिना रोसिन और तारपीन का निर्माण करने वाली इकाइयों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं करने के लाभों का विस्तार करने के लिए; और

(सी) कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करें जो न्यायालय उचित और उचित समझे।"

यह वह रिट याचिका है जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.02.2016 के फैसले के तहत खारिज कर दिया है।

15. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश और अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण का कहना था कि विभाग द्वारा किए गए पुनः सर्वेक्षण से यह स्थापित हुआ है कि भट्टी निर्माताओं से उत्पाद शुल्क की मांग नहीं करने की एक सामान्य प्रथा थी, हालांकि, इस सर्वेक्षण में, केवल लगभग 125 इकाइयों की जांच की जा सकी क्योंकि विभाग को शेष उद्योगों का पूरा विवरण नहीं मिल सका और इसके अलावा, उनमें से अधिकतर लघु उद्योग थे जो एसएसआई छूट के तहत लाभ उठा रहे थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि फिर भी इस सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम से कम 39 इकाइयाँ थीं जिनका कारोबार एसएसआई सीमा से अधिक था, लेकिन उन इकाइयों से भी किसी उत्पाद शुल्क की मांग नहीं की गई थी। अपीलकर्ता ने आयुक्त

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की निम्नलिखित दिनांक 20.05.2014 की नोटिंग पर भरोसा किया:

"11...यह स्पष्ट है कि अधिकांश इकाइयां इस अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थीं और 2 इकाइयों यानी मिस. गुरुकृपा रेजिन्स (पी) लिमिटेड और मिस. दुजोडवाला इंडस्ट्रीज के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। अपंजीकृत इकाइयों के संबंध में कथित तौर पर कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।

अपंजीकृत इकाइयों द्वारा कोई घोषणा दाखिल न करने के कारण स्पष्ट नहीं हैं। यह कर्तव्य का भुगतान न करने का मामला हो सकता है या वैकल्पिक रूप से इन इकाइयों द्वारा यह विश्वास किया जा सकता है कि वे 1978 के टीआरयू स्पष्टीकरण के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। घोषणा पत्र दाखिल न करने के सटीक कारणों को केवल क्षेत्रीय अधिकारी ही बता सकते हैं जिनके पास कथित तौर पर पूरे रिकॉर्ड नहीं हैं। हालाँकि, तथ्य यह है कि कई अपंजीकृत इकाइयों ने एसएसआर सीमा पार करने के बाद भी शुल्क का भुगतान नहीं किया और विभाग ने भी उनसे इस तरह के शुल्क की मांग नहीं की....इसलिए, इसे लेवी के साथ-साथ भुगतान न करने का मामला भी माना जा सकता है..."

अवर सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने अपनी दिनांक 22.08.2014 की नोटिंग में कहा है कि:

"... _पुनः सर्वेक्षण ने संकेत दिया है कि कम से कम 39 अपंजीकृत इकाइयाँ थीं जिनका कारोबार 1994-1995 से 2005-06 के दौरान एक बार या एक से अधिक बार एसएसआई छूट सीमा से अधिक था... यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहाँ शुल्क न लगाने की प्रथा थी।"

अंत में, सदस्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने भी अपनी दिनांक 11.09.2014 की नोटिंग में देखा है;

"... नए सिरे से सर्वेक्षण कर इस मुद्दे की फिर से जांच की गई। यह पाया गया कि यद्यपि शुल्क न लगाने की प्रथा थी, धारा 11 [सी] अधिसूचना जारी करने से केवल दो कंपनियों को लाभ होगा, अर्थात्, मेसर्स गुरुकृपा रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर और मेसर्स.दुजोदवाला इंडस्ट्रीज, मुंबई। तत्कालीन राजस्व सचिव [पी/112 एन.एस.] के अनुमोदन से निर्णय लिया गया था कि धारा 11 [सीजे अधिसूचना केवल कुछ चुनिंदा उद्योगों के पक्ष में जारी नहीं की जा सकती है और अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया था।"

16. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि विभाग की ही एक विशिष्ट खोज थी कि उन इकाइयों पर शुल्क न लगाने की एक प्रचलित प्रथा थी जो समान उत्पादों का निर्माण करती थीं और केवल कूलिंग टैंक में पानी पंप करने के लिए बिजली का उपयोग करती थीं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 11 सी के तहत उल्लिखित शर्तें स्पष्ट रूप से पूरी की गई थीं।

17. उपरोक्त आधार पर आगे बढ़ते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि एक बार एक विशेष वैधानिक प्रावधान की शर्तें पूरी हो जाने के बाद, सरकार एक आवश्यक अधिसूचना जारी करने के साथ शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य थी। यह तर्क दिया गया कि यह शक्ति अधिनियम की धारा 11 सी के तहत कर्तव्य के साथ केंद्र सरकार में निहित है और इसलिए, केंद्र सरकार उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। समर्थन में, जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप और अन्य 1 में प्रिवी काउंसिल के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसके बाद अंबिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य और अन्य में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था..., जहां यह समझाया गया था कि जिस चीज को करने का अधिकार दिया गया है उसकी प्रकृति ही किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में शक्ति का प्रयोग करने का दायित्व लगा सकती है। यह माना गया कि ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब शक्ति का प्रयोग न करने से उस व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इस निर्णय के पैरा 13 पर विशेष रूप से भरोसा किया गया था जो इस प्रकार है:

"13. श्री गोबिंद दास द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त नियम गुजरात लघु खनिज नियम, 1966 के नियम 18 के उप-नियम (बी) के अनुरूप था। अक्सर जब एक सार्वजनिक प्राधिकरण को शक्ति प्रदान की जाती है, अभिव्यक्ति "हो सकता है" का अर्थ "करेगा" के रूप में लगाया गया है क्योंकि यदि अभ्यास की शर्तें पूरी होती हैं तो शक्ति कर्तव्य के साथ जुड़ी होती है। जैसा कि क्रेज़ ऑन स्टैट्यूट लॉ, 7 वें संस्करण, पृष्ठ 229 में देखा गया है, अभिव्यक्ति "हो सकता है" और "होगा" अक्सर निरंतर और परस्पर विरोधी व्याख्या का विषय रहे हैं। "मई" एक अनुमोदक या सक्षम करने वाली अभिव्यक्ति है लेकिन ऐसे मामले भी हैं जिनमें विभिन्न कारणों से जैसे ही कानून के

अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को शक्ति सौंपी जाती है, उसका प्रयोग करना उसका कर्तव्य बन जाता है। 1880 में ही जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप मामले में प्रिवी काउंसिल ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अर्ल केन्स, लॉर्ड चांसलर ने न्यायिक समिति की ओर से बोलते हुए "यह वैध होगा" अभिव्यक्ति से निपटते हुए कहा कि ये शब्द एक संकाय या शक्ति प्रदान करते हैं और वे स्वयं एक संकाय या शक्ति प्रदान करने से अधिक कुछ नहीं करते हैं। लेकिन लॉर्ड चांसलर ने समझाया कि जिस चीज को करने का अधिकार दिया गया है उसकी प्रकृति में कुछ हो सकता है, जिस उद्देश्य के लिए यह किया जाना है उसमें कुछ हो सकता है, जिन परिस्थितियों में यह किया जाना है उनमें कुछ हो सकता है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के शीर्षक में कुछ जिसके लाभ के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ सकता है, और इसे व्यक्ति का कर्तव्य बना सकता है, जिसमें शक्ति सौंपी गई है, जब भी उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, वह उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्या शक्ति एक कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और प्रत्येक मामले में अदालतों द्वारा इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। लॉर्ड ब्लैकबर्न ने उक्त निर्णय में कहा कि सक्षम शब्द हमेशा अनिवार्य थे जहां शब्द कानूनी अधिकार को प्रभावित करने के लिए थे।"

18. विद्वान वकील ने हमारा ध्यान धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में दिए फैसले की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें जूलियस में प्रिवी काउंसिल के फैसले को उस उद्देश्य के लिए आदेश जारी करके उस दायित्व को

लागू करने के बारे में फिर से संदर्भित किया गया था जिसके लिए शक्ति कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त मामले में, न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए सरकार को एक सलाहकार परिषद गठित करने का निर्देश दिया था कि यह सरकार पर निर्भर है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि डी.के.बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य मामले में भी यही दृष्टिकोण और कानूनी स्थिति निर्धारित की गई है, जहां यह माना गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की राज्य सरकारों की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई शक्ति थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह प्रभावित नागरिकों के न्याय तक पहुंचने के अधिकार को छूती थी, जो कि अनुच्छेद 21 द्वारा कवर किया गया एक मौलिक अधिकार था। राज्य सरकार के उक्त कर्तव्य को तदनुसार न्यायालय द्वारा समयबद्ध अवधि के भीतर आयोगों की स्थापना/रक्तियों को भरने के लिए एक परमादेश या निर्देश जारी करके लागू किया गया था। अनीसली लावांडे और अन्य बनाम गोवा राज्य और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने उस दायित्व को लागू करने का निर्देश दिया, जिसे सरकार को प्रदत्त शक्ति से जुड़ा माना गया था। इसी पहलू पर सुरेश चंद्र गौतम बनाम उत्तर राज्य प्रथमलेश एवं अन्य का भी संदर्भ दिया गया था।

19. अपीलकर्ता के वकील की एक अन्य दलील यह थी कि अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग न करने के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एकमात्र कारण यह था कि ऐसी अधिसूचना, यदि जारी की जाती है, तो केवल दो निर्धारितियों को लाभ होने वाला था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकार के लिए इस तरह की अधिसूचना को अस्वीकार करने का यह कभी भी वैध या तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता है, खासकर उस स्थिति में जहां मांग नोटिस केवल दो निर्धारितियों को जारी किए गए थे और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को बखशा गया था। विद्वान

वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने अतीत में व्यक्तिगत मामलों में अधिनियम की धारा 11 सी के तहत एक अधिसूचना जारी की थी, जहां न्यायालय का लाभ केवल एक पहचाने गए निर्धारिती को है। इसी आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा विकसित एक और दलील यह थी कि भेदभाव को दूर करने के लिए उक्त प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी करना अधिक आवश्यक और अनिवार्य हो गया है। विभाग द्वारा केवल दो निर्धारितियों को शामिल करके और समान रूप से रखे गए अन्य निर्धारितियों से उत्पाद शुल्क की मांग न करके कौन सी स्थिति बनाई गई थी। अपीलकर्ता के अनुसार, अधिसूचना जारी न करने से संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 19 (एल) (जी) के तहत अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि सरकार इस दलील के तहत आश्रय नहीं ले सकती कि अधिनियम की धारा 1 आईसी के तहत शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति थी और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी थी। दलील यह थी कि इस प्रकृति का परमादेश पहले भी जारी किया जा चुका है। क्लॉकसी ट्यूब कंपनी लिमिटेड बनाम भारत सरकार और अन्य तथा भारत सरकार और अन्य बनाम एन.एस.रत्नमम एंड संस शीर्षक वाले मामलों का उदाहरण दिया गया।

20. यह भी तर्क दिया गया कि रिट याचिका दायर करने में अपीलकर्ता की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी और इस संबंध में प्रतिवादी की आपत्ति अस्थिर थी। मंत्री का अस्वीकृति आदेश सितंबर, 2014 में आया और उसके तुरंत बाद रिट याचिका दायर की गई। अपीलकर्ता को उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करने का एकमात्र कारण यह था कि वह अपने द्वारा दायर रिट याचिका में अंतरिम रोक प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के सफल होने की स्थिति में, अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि को उस दर पर ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया जाना चाहिए, जिसे यह न्यायालय उचित मानता है।

21. उपरोक्त दलीलों का समान दृढ़ता के साथ प्रतिवाद करना और अपने निष्कर्ष के समर्थन में आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को भी अपनाना, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए.के. सांघी ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 सी एक सक्षम प्रावधान है, जिसने केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं पर देय संपूर्ण उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं करने या देय सामान्य शुल्क से कम उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया। उन्होंने धारा 11 सी के शुरुआती शब्दों पर जोर दिया, यानी 'उत्पाद शुल्क वसूल न करने की शक्ति...'. इस प्रकार, उनका तर्क यह था कि यह एक प्रावधान है जो सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने का अधिकार देता है और इसलिए, यह शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है। उनका आगे कहना था कि चूंकि शुल्क की छूट आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके हो सकती है, ऐसी शक्ति अधीनस्थ कानून की प्रकृति में थी और स्थापित कानून के अनुसार, अदालतें वैधानिक कार्य करने के लिए कोई भी परमादेश जारी करने से बचती हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने वैध कारणों से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं करने का फैसला किया है। उनके अनुसार, अधिसूचना जारी न करने का कारण, अर्थात्, यह केवल दो पक्षों को लाभ पहुंचाना था, एक वैध कारण था और अधिनियम की धारा 11 सी के तहत शक्ति का प्रयोग न करने के लिए लिया गया ऐसा नीतिगत निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं था। इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उनकी एक और दलील यह थी कि सरकार द्वारा की गई कवायद, जिसकी परिणति शक्ति का प्रयोग न करने के पूर्वोक्त निर्णय में हुई, वैध और न्यायसंगत आधारों पर आधारित थी, जो वैध विचारों पर आधारित था और न्यायालय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं लेगा।

22. उपरोक्त तर्क पर विस्तार करते हुए, श्री सांघी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ जिन्हें ध्यान में रखा जाना था, कि अपीलकर्ता के साथ-साथ गुरुकृपा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और गुरुकृपा के मामले में कानूनी स्थिति अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2011 के निर्णय के अनुसार निर्धारित की गई थी। क्लिंग टैंक में पानी उठाने की प्रक्रिया सामान के निर्माण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी और इसलिए, यदि पानी उठाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है, तो छूट उपलब्ध नहीं होगी। श्री सांघी का तर्क यह था कि एक बार यह स्थिति कानूनी रूप से तय हो जाने के बाद, अपीलकर्ता के लिए अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी करने के निर्देश की मांग करके उक्त निर्णय के प्रभाव को रद्द करना संभव नहीं था।

23. उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार के लिए तीन मुद्दे उठते हैं - पहला प्रश्न यह है कि क्या ये शर्तें तत्काल मामले में पूरी होती हैं? दूसरे, यदि यह पाया जाता है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं अधिनियम के तहत शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन आम तौर पर शुल्क की मांग न करने या शुल्क न लगाने, या ऐसे सामानों पर कम शुल्क की मांग करने की प्रथा प्रचलित रही है, क्या केंद्र सरकार के लिए अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी करना अनिवार्य है कि ऐसी वस्तुओं पर कोई शुल्क देय नहीं होगा या कम शुल्क देय होगा? तीसरा, यदि सरकार इस 'शक्ति' का प्रयोग नहीं करना चाहती है, तो क्या न्यायालय अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी अधिसूचना पारित करने के लिए केंद्र सरकार को एक परमादेश जारी कर सकता है?

हमने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि यह मामला इसमें शामिल मुद्दों के अनुरूप है।

प्रश्न संख्या 1

24. प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की जा सकती है कि, निस्संदेह, जहां तक अपीलकर्ता द्वारा निर्मित और बिक्री के लिए मंजूरी दे दी गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क का सवाल है, वह उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय है। यह अपीलकर्ता का अपना मामला है कि गुरुकृपा रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 11.07.2011 के फैसले से पहले इस संबंध में कानूनी स्थिति कुछ हद तक अस्थिर और अनिश्चित थी। वे इकाइयाँ जो सभी प्रक्रियाओं में बिजली का उपयोग करके रोसिन और टर्पेन्टाइन का निर्माण करती हैं, यानी वैक्यूम रासायनिक उपचार प्रक्रिया, उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थीं और भुगतान भी कर रही थीं। हालाँकि, जहाँ तक भट्टी प्रक्रिया को अपनाने वाली इकाइयाँ (अपीलकर्ता किस श्रेणी का है और) का सवाल है, जिसमें पूरी प्रक्रिया मैनुअल है, एक प्रक्रिया को छोड़कर, अर्थात् संघनित करने के उद्देश्य से पानी को भंडारण टैंक तक उठाने के लिए पंप को संचालित करने के लिए बिजली का उपयोग) यह सवाल है कि क्या यह प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया की श्रेणी में आएगी या नहीं, अस्पष्ट था। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश इकाइयाँ जो भट्टी पद्धति का सहारा ले रही थीं, लघु पैमाने की इकाइयाँ थीं और उस आधार पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का आनंद ले रही थीं। इसलिए, वे किसी भी स्थिति में राजस्व के दायरे में नहीं थे। पांच पंजीकृत इकाइयाँ उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रही थीं। विभाग ने उन दो इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो उसके साथ पंजीकृत थीं लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थीं। जैसा कि राजस्व के अनुसार, टैंकों में तरल तारपीन के रूप में एकत्रित तारपीन वाष्प के संघनन के लिए ओवरहेड टैंकों में पानी उठाने के लिए बिजली का उपयोग भी विनिर्माण प्रक्रिया होगी और इसलिए, उत्पाद शुल्क देय होगा। अन्य पंजीकृत नहीं थे और एसएसआई इकाइयाँ थीं। ऐसा हुआ कि किसी समय, उनमें से कुछ एसएसआई इकाइयाँ नहीं रह

गई। लेकिन, विभाग इससे अंजान बना हुआ है। इसी कारण अन्य को नोटिस जारी नहीं किया जा सका। जब मामले को उपरोक्त कोण से देखा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पाद शुल्क की वसूली न करने की एक सचेत प्रथा आम तौर पर प्रचलित थी।

25. निस्संदेह, एसोसिएशन के अनुरोध पर और उसके अनुरोध पर, यह पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करवाया गया था कि क्या इस संबंध में कोई सामान्य प्रथा थी या नहीं। पहले सर्वेक्षण का परिणाम अपीलकर्ता के लिए प्रतिकूल था क्योंकि पंजीकृत इकाइयों के संबंध में, सर्वेक्षण से पता चला कि ऐसी इकाइयों द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं करने की सामान्य प्रथा स्थापित नहीं की गई थी। यह देखा गया कि पांच पंजीकृत इकाइयां पूरी अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान कर रही थीं। दो इकाइयों ने शुल्क का भुगतान नहीं किया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे (ये अपीलकर्ता और गुरुकृपा हैं)। जिस एसोसिएशन का अपीलकर्ता सदस्य था, उसने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त 250 इकाइयों की एक सूची भेजी थी। हालाँकि, जो पाया गया वह यह था कि ये इकाइयाँ अपंजीकृत थीं और एसएसआई के तहत मानी गई थीं और इसलिए, इन कारणों से, उनसे उत्पाद शुल्क की मांग नहीं की गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि शुल्क न माँगने की सामान्य प्रथा थी। एसोसिएशन ने नए सिरे से सर्वेक्षण की मांग की और एक मंत्री के समर्थन से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ।

26. अपीलकर्ता के अनुसार, दूसरे सर्वेक्षण में, यह सामान्य प्रथा स्थापित हुई। इस प्रयोजन के लिए, अपीलकर्ता आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की दिनांक 20.05.2014 की नोटिंग के कुछ उद्धरणों पर भरोसा कर रहा है। उक्त नोटिंग, जब पूरी तरह से पढ़ी जाती है, तो स्पष्ट रूप से ऐसी किसी भी प्रथा को स्वीकार नहीं करती है। इससे पता चलता है कि दूसरे सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 37 अपंजीकृत इकाइयों ने

कम से कम एक बार एसएसआई छूट सीमा पार कर ली थी, लेकिन वे संबंधित अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे। इससे निदेशक ने अपने नोट में पाया कि शुल्क का भुगतान नहीं करने की प्रथा थी। हालाँकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने अपने दिनांक 20.05.2014 के नोट में विशेष रूप से कहा कि वह निदेशक द्वारा निकाले गए उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं थे, जो अत्यधिक विवादास्पद था। उन्होंने टिप्पणी की कि कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना, राजस्थान में इस न्यायालय के फैसले के बावजूद, प्रासंगिक प्रश्न यह था कि क्या प्रासंगिक अवधि के दौरान शुल्क लगाने और न लगाने का चलन था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम की धारा 11सी तभी लागू होती है जब कानूनी तौर पर शुल्क लगाया जाता है लेकिन फिर भी शुल्क न लगाने की प्रथा है।

27. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग इस धारणा में रहा कि वे इकाइयाँ जो अपंजीकृत थीं और एसएसआई स्थिति के कारण उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थीं, वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थीं और इसलिए, उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। यहां तक कि जब 37 अपंजीकृत इकाइयों ने कम से कम एक बार एसएसजे छूट सीमा को पार कर लिया था, तब भी उत्पाद शुल्क विभाग या तो अपनी लापरवाही के कारण उन्हें पकड़ नहीं सका या उसे यह विश्वास था कि वे अभी भी छूट का आनंद ले रहे थे। दूसरे सर्वेक्षण के दौरान ही ये तथ्य विभाग की नजर में आये. यह रिकॉर्ड में आया है कि उस समय तक उनसे शुल्क की वसूली बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये मामले कालातीत हो गए थे, जिसका अर्थ है कि यदि ये मामले सीमा अवधि के भीतर होते, तो विभाग ने उनसे शुल्क वसूलने की भी कार्रवाई की होती। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य प्रथा थी। निःसंदेह, कुछ अधिकारियों ने उपरोक्त को शुल्क न लगाने का मामला मानकर इसके विपरीत राय बना

ली है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस तरह के दृष्टिकोण को बहस योग्य बताया गया था। केवल इसी कारण से मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया और इस आधार पर कार्रवाई की गई कि ऐसी प्रथा थी लेकिन फिर भी धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी होने पर इसका लाभ केवल दो इकाइयों को ही मिलेगा। इसे आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की दिनांक 20.05.2014 की निम्नलिखित नोटिंग के पैराग्राफ 13 से देखा जा सकता है:

"13. इस संबंध में, जैसा कि यू.एस. द्वारा पृष्ठ 97/एनएस पर बताया गया है, किसी भी 11 सी अधिसूचना का लाभ केवल 2 इकाइयों को उपलब्ध होगा। 1994-2006 की अवधि के लिए अपंजीकृत इकाइयों को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पहले से ही कालातीत है। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर व्यापार प्रभावित नहीं होता है। F.No.52/2/2008-CX.I में, पहले एक दृष्टिकोण लिया गया है कि धारा 11 सी के प्रावधान असाधारण हैं और आम तौर पर बड़े पैमाने पर व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर लागू होते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के खिलाफ दिए गए शीर्ष न्यायालय के न्यायिक निर्णय को ओवरराइड करने के लिए धारा 11 सी को एक या दो व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू नहीं किया जाता है।"

28. जब सभी तथ्यों को समग्रता से ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि उत्पाद शुल्क नहीं लगाने की सामान्य प्रथा के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इस धारणा के तहत कि इसकी मांग पंजीकृत इकाइयों से की जानी थी और पांच ऐसी पंजीकृत इकाइयां वास्तव में शुल्क का भुगतान कर रही थीं, शेष दो इकाइयों, अर्थात् अपीलकर्ता और गुरुकृपा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। यह स्वयं उत्पाद शुल्क न लगाने की सामान्य

प्रथा के अस्तित्व के तर्क को नकारता है। यह दोहराने की कीमत पर कहा गया है कि केवल इसलिए कि कुछ अपंजीकृत फर्म जिन्हें शुरू में एसएसआई छूट मिल रही थी, लेकिन एसएसआई सीमा पार करने पर अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया था, हमारी राय में, ऐसी कोई प्रथा स्थापित नहीं की जाएगी।

29. इस संबंध में, यह भी उजागर करने की आवश्यकता है कि जहां तक विभाग का संबंध है, उसने एक स्पष्ट रुख अपनाया था कि वे इकाइयां भी जो तारपीन और रोजिन के निर्माण के लिए भट्टी पद्धति का उपयोग कर रही हैं, अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और यही कारण था कि दोनों इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह दृष्टिकोण, जिसे विभाग ने नोटिस जारी करते समय व्यक्त किया था, गुरुकृपा रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सही साबित हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि उक्त फैसले के बाद अपीलकर्ता ने भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। अब पूरा प्रयास अधिनियम की धारा 11 सी के तहत एक अधिसूचना जारी करके उक्त शुल्क को वापस वसूलने का है। हमारी समझ से ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्या 2 और 3

प्रश्न संख्या 1 के हमारे उत्तर को देखते हुए, इन दो प्रश्नों से निपटना आवश्यक भी नहीं हो सकता है। हालाँकि, चूँकि विभाग स्वयं इस आधार पर आगे बढ़ा कि एक सामान्य प्रथा थी, हम इन मुद्दों पर भी गुण-दोष के आधार पर चर्चा करना चाहेंगे। इन्हें चर्चा के लिए एक साथ लिया जा सकता है।

30. जहां तक ऐसी अधिसूचना जारी करने के सरकार के दायित्व पर आधारित तर्क का संबंध है, प्रशासनिक क्षमता में कार्य करने के कर्तव्य और वैधानिक कार्य करने की शक्ति के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को

कोई कार्य करने के लिए कोई कर्तव्य सौंपा गया है और वह उस कार्य का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो उक्त प्राधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। हालाँकि, यह किसी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय किया जाता है। यह किसी विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा से बिल्कुल अलग है।

31. डी स्मिटल्टन के अनुसार, निम्नलिखित कानूनी परिणाम उपरोक्त भेद से उत्पन्न होते हैं:

(i) यदि कोई आदेश विधायी प्रकृति का है, तो उसे एक निश्चित तरीके से प्रकाशित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि यह प्रशासनिक प्रकृति का है तो यह आवश्यक नहीं है।

(ii) यदि कोई आदेश विधायी है, तो अदालत इसे रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी नहीं करेगी, लेकिन यदि कोई आदेश एक प्रशासनिक आदेश है और प्राधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी करके इसे रद्द कर सकता है।

(iii) आम तौर पर, अधीनस्थ कानून को अनुचितता के लिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि इसकी अनुचितता दुर्भावना का सबूत न हो या अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग न दर्शाती हो। लेकिन अनुचित प्रशासनिक आदेश के मामले में, पीड़ित पक्ष कानूनी उपचार का हकदार है।

(iv) केवल अधिकांश असाधारण परिस्थितियों में ही विधायी शक्तियां उप-प्रत्यायोजित की जा सकती हैं, लेकिन प्रशासनिक शक्तियां उप-प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

(v) कारण बताने का कर्तव्य प्रशासनिक आदेशों पर लागू होता है, लेकिन कानून बनाने के आदेशों पर नहीं।

32. अधिनियम की धारा 11C के तहत अधिसूचना जारी करना अधीनस्थ कानून की प्रकृति में है। सरकार को इस तरह की अधिसूचना जारी करने का निर्देश देना नीतिगत निर्णय को दयनीय तरीके से लेना होगा, जो अनुचित है। इस न्यायालय ने हाल ही में जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम आर.कृष्णमूर्ति के मामले में इस पहलू पर विचार किया। उक्त निर्णय से निम्नलिखित चर्चा उपयोगी है और उद्धरण के लायक है:

"25. नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप और एक विशेष तरीके से नीति तैयार करने के लिए परमादेश जारी करना बिल्कुल अलग है। अधिनियम ने केंद्र सरकार को जनगणना करने के तरीके के बारे में अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की है और केंद्र सरकार ने अधिसूचनाएं जारी की हैं, और सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। कानून बनाना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अदालतें कानून की व्याख्या करती हैं और ऐसी व्याख्या में कुछ रचनात्मक प्रक्रिया शामिल होती है। कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार न्यायालय को है। वह भी वहीं, जहां इसकी मांग होती है। न्यायालय संवैधानिक चुप्पी या स्थगन के सिद्धांत को लागू करके कुछ क्षेत्रों में अंतराल को भी भर सकता है। लेकिन, अदालतों को परमादेश रिट जारी करके नीति में कुछ जोड़कर नीति निर्माण में नहीं उतरना चाहिए। वहां न्यायिक संयम का आह्वान इस बात को याद रखने के लिए किया जाता है कि हमने शुरुआत में क्या कहा है। न्यायालयों को कार्यपालिका द्वारा तय किये गये नीतिगत निर्णयों को समझना

आवश्यक है। यदि कोई नीतिगत निर्णय या अधिसूचना मनमाना है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 की आलोचना का कारण बन सकता है। लेकिन जब अधिसूचना पर कोई रोक नहीं थी और वह अधिनियम के अनुरूप है, तो यह वास्तव में समझ से परे है कि उच्च न्यायालय कुछ पहलुओं को जोड़कर किस तरीके से जनगणना की जाएगी, इस बारे में निर्देश कैसे जारी कर सकता है। वास्तव में, यह एक विशिष्ट तरीके से नीति तैयार करने के लिए एक निर्देश जारी करना है।

26. इस संदर्भ में, हम सुरेस्लज सेठ बनाम कॉमरेड, आई 11 डोर म्यू 11 इसिपल कॉरपोरेशन: (2005) 13 एससीसी 287 में तीन-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष मद्रास नगर निगम अधिनियम, 1956 में उचित संशोधन के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी ताकि एक व्यक्ति को एक साथ दो निर्वाचित पदों पर रहने से रोका जा सके, अर्थात्, विधान सभा के सदस्य का और नगर निगम के मेयर का भी। उक्त दलील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:

"हमारी राय में, यह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को तय करने का नीतिगत मामला है और इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह न्यायालय विधायिका को किसी विशेष प्रकार का अधिनियम बनाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है।" संवैधानिक योजना के तहत संसद और विधानसभाएं जॉज को अधिनियमित करने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती हैं और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर

सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ MANU/SC/0582/1989:(1989) 4 SCC 187 (SCC पैरा 51) में यह माना गया है कि कोई भी अदालत किसी विधायिका को एक विशेष कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। इसी प्रकार, जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी विधायिका के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी को कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे उसे प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकार के तहत करने का अधिकार दिया गया है। यह दृष्टिकोण जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम ए.आर.जक्की मनु/एससी/0293/1992: एल 992 सप्प (1) एससीसी 548 में दोहराया गया है। ए.के.रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मनु/एससी.0051/1981:(1982) 1 एससीसी 271 में यह माना गया कि विधायिका द्वारा पारित अधिनियम को लागू करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

29. इस संदर्भ में, रुसोम कैवासी कूपर बनाम भारत संघ MANU/SC/0011/1970: (1970) 1 धारा 248 में प्राधिकार का उल्लेख करना उपयोगी है, जिसमें इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है:

"यह फिर से इस न्यायालय का काम नहीं है कि वह विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों या आर्थिक नीतियों के सापेक्ष गुणों पर विचार करे... इस न्यायालय के पास अधिकार की कमी के आधार पर किसी कानून को रद्द करने की शक्ति है लेकिन न्यायालय कानून बनाने में संसद की नीति पर अपील में नहीं बैठेगा।"

33. जैसा कि उक्त निर्णय के निकाले गए हिस्से से देखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ" में, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि कोई भी अदालत किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए विधायिका को निर्देश नहीं दे सकती है। इसी प्रकार जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी विधायिका के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी को वह कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसे उसे प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकार के तहत करने का अधिकार दिया गया है।

34. हम कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य¹⁴ के मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। उस मामले में, हालांकि विधायिका ने दिल्ली किराया अधिनियम में संशोधन किए थे, लेकिन उक्त संशोधनों के लागू होने की तारीख को अधिसूचित करना सरकार पर छोड़ दिया गया था। सरकार ने कोई तारीख अधिसूचित नहीं की। तारीख अधिसूचित करने के लिए सरकार को परमादेश जारी करने की मांग करते हुए एक रिट दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उपरोक्त निर्णय में उक्त निर्णय को मंजूरी देते हुए न्यायालय ने इस विषय पर पहले के विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया। यह माना गया कि न केवल संसद को कार्यपालिका को ऐसी शक्ति देने का अधिकार है कि वह यह तय कर सके कि अधिनियम को कब लागू किया जाए, बल्कि यह भी माना गया कि संशोधनों को अधिसूचित करने के लिए सरकार को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ भी कीं जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं:

"27. हमारे सामने रखे गए तथ्यों से यह नहीं कहा जा सकता

कि सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं है या संसद की इच्छा

की अनदेखी करना चाहती है, जब विधायिका ने अधिनियम लागू होने की तारीख को अधिसूचित करने की शक्ति स्वयं केंद्र सरकार में निहित कर दी थी, तब, अधिनियम को कब लागू किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय केंद्र सरकार ऊपर दिए गए तथ्यों सहित विभिन्न तथ्यों पर विचार करने की हकदार है। रिकॉर्ड में लाए गए तथ्यों और इस न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा एल (3) के तहत विचार की गई अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

35. अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों का तत्काल मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सभी निर्णय प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति निश्चित रूप से तब मौजूद होती है जब यह पाया जाता है कि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण/कार्यकारी अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है।

36. इस मामले को दूसरे नजरिये से भी देखा जा सकता है. जब केंद्र सरकार को इस आशय की अधिसूचना जारी करने की 'शक्ति' दी जाती है कि उत्पाद शुल्क की वसूली न की जाए या अधिनियम के तहत सामान्य रूप से देय शुल्क से कम शुल्क की वसूली की जाए, तो यह तय करने के लिए कि ऐसी अधिसूचना जारी की जाए या नहीं, सरकार के मन में कई तरह के विचार हो सकते हैं. केवल इसलिए कि उक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हैं, ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई कारण नहीं होगा। यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है. इसमें कोई संदेह नहीं है, मनमानी के खिलाफ सिद्धांत को अधीनस्थ कानून तक भी बढ़ाया गया है (देखें: इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र, बॉम्बे बनाम भारत संघ-'). वहीं, ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत

सीमित है। जहां कानून एक प्रशासनिक प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, न्यायालय ऐसे विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह अप्रत्यक्ष अंत या बाहरी उद्देश्यों या बाहरी विचारों पर या मनमाने ढंग से, प्रासंगिक विचारों पर अपना दिमाग लगाए बिना नहीं किया जाता है। या जहां यह किसी भी मानदंड द्वारा निर्देशित नहीं है जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।

37. प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार की नीति अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी नहीं करना है, जब इससे केवल कुछ निर्धारितियों को लाभ होता है। बताया गया है कि सरकार की विशिष्ट नीति यह है कि जब व्यापार का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है और कोई राहत देने का प्रस्ताव होता है, तो अधिनियम की धारा 11 सी के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है। जब सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग न करने के कारणों को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, अर्थात्, ऐसी अधिसूचना, यदि जारी की जाती है, तो केवल दो इकाइयों को लाभ होने वाली है, हम उन्हें वैध और उचित पाते हैं। मैट्रिया केमिकल्स लिमिटेड आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि 16 के मामले में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की संवैधानिक वैधता की चुनौती से निपटते समय, इस न्यायालय ने कहा कि विधायिका बकाया वसूलने के लिए त्वरित कानूनी पद्धति अपनाने की नीति के तहत उक्त कानून लेकर आई है। यह माना गया कि विधायिका के इस तरह के नीतिगत निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है और न ही वित्तीय नीति से संबंधित इस तरह के उपाय की वैधता का परीक्षण करने के लिए अदालतों द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, इस न्यायालय के लिए ऐसे नीतिगत निर्णय के साथ छेड़छाड़ करना अस्वीकार्य है, खासकर जब यह पाया जाता है कि निर्णय तर्कहीन

नहीं है और वैध विचारों पर आधारित है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने पहले ही शुल्क का भुगतान कर दिया है। धारा 11 सी उन स्थितियों पर विचार करती है जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें वह स्थिति शामिल नहीं है जहां शुल्क का भुगतान किया गया है और उसे वापस किया जाना है।

38. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच से अपीलकर्ताओं के अधिकांश तर्कों का उत्तर मिल जाएगा। यह न तो भेदभाव का मामला होगा और न ही यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के पास संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत कोई अधिकार है, जिसका अधिनियम की धारा 11 सी के तहत अधिसूचना जारी न किये जाने से उल्लंघन किया गया है। एक बार जब अपीलकर्ता यह स्वीकार कर लेता है कि कानून के अनुसार वह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही कुछ इकाइयाँ कुछ कारणों से शुल्क के भुगतान से बचने में सफल रही हों, अपीलकर्ता यह नहीं कह सकता कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उपयोग करके उससे कोई शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड एक सकारात्मक अवधारणा है और इसे नकारात्मक रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

39. परिणामस्वरूप, यह अपील किसी भी योग्यता से रहित पाई गई और तदनुसार, खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे

अपील खारिज.

(यह अनुवाद एआई टूल: सुवास की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।